Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): The resolution, which is before the House, lays stress on the fact that there is lack of proper arrangement of irrigation, electrification and drinking water in rural sector. It was moved with the object of bringing this fact into light that due emphasis has not been laid on agriculture in Fourth Five Year Plan. The resolution is simple one.

If there is anything in this country which requires special attention, that is agriculture. What is required to improve agriculture and to increase agricultural production is water, electricity and manure. But the main necessity is that of water.

Some big people, officers and advisers, who are American-oriented, are of the opinion that Indian farmers do not know how to cultivate and they require technical know-how. They ask people to grow more food. In my opinion nothing more than water at proper time is required for agriculture in India. If water is made available for agriculture, agricultural production can be increased by hundred per cent. Here we do not require technical know-how, American fertilizers or personnel of American Peace Corps. Manure or fertilizer is required in Madras, Andhra Pradesh and Kannad area where adequate water has been made available for irrigation purposes. In some districts of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Punjab we require water for irrigation. The soil we till requires more water than fertilizers.

In the present plan outlay for every sector has been doubled, but in respect of irrigation instead of doubling the outlay, it has been increased to only 750 crores from 550 or 650 crores. It is absolutely insufficient for 500 minor irrigation projects under construction in the country. It is asserted that irrigational potential in the country will be increased to 3 crores of acres. How this amount of 750 crores will help irrigation schemes in the country, how it will solve food problem or in being self-dependent in matter of food. If sufficient allotment is made for irrigation we will soon be self-dependent in respect of food.

Govt. should also pay attention towards its administrative machinery. It fits in absolute police state. It is not suitable for welfare state. All the last three plans show that we have sufficient resources. We have anyhow managed the outlays required for all the Plans. Though we achieved financial targets of the Plans yet badly failed in achieving physical targets. There has not been any increase in national income. People speak against Public Sector but what are the returns received from Private Sector, though we have given too much to it. The main point which should be well understood is that every Plan in our country must be village-oriented. We should never forget it.

## स्वर्ण नियंत्रण में ढील देने के बारे में वक्तव्य STATEMENT RE: RELAXATION OF GOLD CONTROL

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) श्रीमान्, संसद के पिछले अधिवेशन में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान स्वर्ण नियंत्रण का प्रश्न उठाया गया था। इस समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए एक अनौपचारिक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है।

समिति का मुख्य निष्कर्ष यह है कि जब से संसद ने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1965

बनाया है, तब से ऐसी कोई महत्वपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय बात नहीं हुई है जिसके कारण मूल स्वर्ण नीति में कोई परिवर्तन किया जा सके।

सरकार सिमित के निष्कर्ष से सहमत है परन्तु वह समझती है कि सामाजिक—आर्थिक सुधार के लिए किये गये वे उपाय, जिनसे कई शताब्दी पुरानी प्रणाली तथा रीतियों में परिवर्तन करना हो, कुछ ही वर्षों में प्रभावी नहीं हो सकते। धीरे धीरे परन्तु लगातार देश में स्वर्ण के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रतिबन्ध लगाना होगा। इन मूल बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निश्चय किया है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अधीन 14 कैरेट से अधिक के सोने के आभूषण बनाने पर लगे प्रतिबन्ध हटाये जायें। इससे बहुत से स्वर्णकारों को लाभ होगा और सभा में और सभा के बाहर जो सुझाव रखे गये हैं और जो आलोचना की गई है, उनको काफी हद तक तुष्ट किया जा सकेगा। यह निश्चित करने के लिए कि इस ढील से स्वर्ण का तस्कर व्यापार न बढ़े, हमारी स्वर्ण नीति के दीर्घकालीन उद्देश्य पूरे करने के लिये कुछ अन्य उपाय करना अनिवार्य होगा।

सरकार का विचार है कि स्वर्ण को मूल भूत रूप में अर्थात छड़ें, सिलें, पटिया, बिलेट, गोलियां, शलाकायें, राड और तार रखने को निषिद्ध किया जाये। जिन लोगों के पास मूलभूत रूप से स्वर्ण वैध रूप में है या जिन्होंने स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अधीन सोने के सम्बन्ध में घोषणा कर दी है और जिनके पास छूट दी हुई सीमा के अन्दर सोना है, उनको उचित समय दिया जायेगा ताकि वे या तो उसे लाइसेंसदार व्यापारियों को बेच दें या आभूषणों में परिवर्तित कर दें। इस प्रकार आभूषण बनाने के लिये बाजार में अधिक स्वर्ण उपलब्ध हो सकेगा।

सोना साफ करने वाले कारखानों को सरकारी नियंत्रण में लाया जायेगा और बाद में उन्हें राज्य के स्वामित्व में लाया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि तस्कर रूप में लाया हुआ स्वर्ण अबाध रूप से आभूषणों में परिवर्तित न किया जा सके, उन लोगों को यह घोषणा करनी होगी, जिनके पास उस सीमा से अधिक, जो निर्धारित की जायेगी, स्वर्ण आभूषण हैं। वह सीमा इस प्रकार निश्चित की जायेगी जिससे ऐसे अधिकांश लोगों को ऐसी घोषणा न करनी पड़े जिनके पास उचित मात्रा में स्वर्ण आभूषण हैं।

राजकोषीय नीतियां और सार्वजनिक शिक्षा इस प्रकार बनाई जायेगी कि लोगों को स्वर्ण के प्रयोग करने की आदत छुड़ाई जा सके क्योंकि इसके कारण हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। सरकार इन परिवर्तनों को आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं करने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र लागू करना चाहती है।

श्री रंगा (चित्तूर): मेरा मुझाव है कि सरकार सभी स्वर्णकारों की रिहाई के लिये तुरन्त कार्यवाही करे।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर): विभिन्न राज्यों में तथा दिल्ली में भी दस भूख हड़ताली अभी तक जेलों में हैं। उन सभी को रिहा किया जाना चाहिये। श्री हिर विष्णु कामत (होशंगाबाद): प्रधान मंत्री को अपने वक्तव्य के अन्त में उन सभी स्वर्णकारों के बारे में कहना चाहिये था जिन्हें आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और अवैध रूप से अवरुद्ध किया गया था।

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना): मैं माननीय सदस्यों के इन विचारों का समर्थन करता है कि गिरफ्तार किये गये सभी स्वर्णकार रिहा किये जायें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): All those goldsmiths should be released. The jail authorities have not behaved properly with the persons arrested day before yesterday. A person named Jaswant Singh was beaten. Should such a behaviour be meted out to the demonstrators.

श्रीमती इन्दिरा गांधी: हम स्वर्णकारों की रिहाई के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे भूख-हड़ताल छोड़ दें।

## योजनाओं के पुनर्विन्यास के बारे में संकल्प-जारी

RESOLUTION RE: REORIENTATION OF PLANS-Contd.

Shri Sheo Narain (Bansi): I should be given an opportunity to speak on this resolution. I move that the time for this resolution may be extended by one hour.

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें ।

Shri Sheo Narain: My motion should be put to vote.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं । वह कृपया बाहर चले जायें ।

Shri Sheo Narain: I am entitled to move a motion.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें अथवा सभा से उठकर बाहर चले जायें ।

श्री शिव नारायण: मैं बाहर चला जाऊंगा।

## श्री शिव नारायण सभा भवन से चले गये ] Shri Sheo Narain left the House

श्री रंगा (चित्तूर): मैं इस संकल्प से सहमत हूं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की लगातार उपेक्षा करती रही है। उसने सिंचाई, ग्रामों में जल ब्यवस्था करने की योजना और वहां विद्युत देने की ओर बहुत कम ध्यान दिया है।

हमारे देश के बहुत से भागों में कई सप्ताह तथा कई मास तक कोई जल नहीं मिलता और लोगों को जल के लिये मीलों तक जाना पड़ता है। सदन को रायलसीमा और राजस्थान